IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP) : उद्देश्य एवं चुनौतियाँ

National Education Policy 2020 (NEP): Objectives and Challenges

राजकुमार वर्मा
शोधार्थी, भूगोल विभाग
राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चूरू (राज.)

सारांशः–

शिक्षा के सम्बन्ध में गाँधी जी का कहना था कि "बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है।" इसी प्रकार स्वामी विवेकानन्द का कहना था कि "मनुष्य की अंर्तनिहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।" इन्हीं सब चर्चाओं के मध्य हम देखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी क्या कमियाँ रह गई थी जिन्हें दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (New National Education Policy-2020) को लाने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही क्या यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन सभी उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिसका स्वप्न महात्मा गाँधी और स्वामी विवेकानन्द ने देखा था? सबसे पहले 'शिक्षा' क्या है इस पर गौर करना आवश्यक है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने एवं सिखाने की क्रिया परन्तु अगर इसके व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में चलने वाली वह निरंतर प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मानव की आन्तरिक शक्तियों का विकास करना और उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना है।

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 21वी सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को मंजूरी दी है अगर उसका क्रियान्वयन सही तरीके से होता है तो यह नई शिक्षा नीति भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले जाएगी।

मुख्य शब्दः– सर्वोत्कृष्ट, अर्न्तनिहित, अभिव्यक्त, क्रियान्वयन, समकक्ष।

प्रस्तावनाः–

आजादी के बाद भारत में पहली शिक्षा नीति सन् 1968 में पूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के समय शुरू की गई थी इसके बाद अगली (दूसरी) शिक्षा नीति राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में बनाई गई जिसमें नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 में कुछ बदलाव किये थे।

नई शिक्षा नीति 2020, 34 साल बाद देश में लागू की जा रही है। नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व इसरो के प्रमुख के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई। जिसमें स्कूली शिक्षा लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किये गये है। नई शिक्षा नीति 2020 के लिए समिति का गठन जून, 2017 में पद्मभूषण प्राप्त डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में किया गया। समिति ने मई 2019 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा कैबिनेट को प्रस्तुत किया गया। 29 जुलाई 2020 को इस मसौदे को केन्द्रीय केबिनेट ने मंजूरी दे

दी। यह शिक्षा नीति 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति के तहत देश की कुल जीडीपी का 6 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जायेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता क्यों?

- बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी।
- शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी।
- भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है –

1. **स्कूली शिक्षा में सुधार** – नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है।

नया फॉमेट	चरण	आयु	कक्षा स्तर
5	फाउण्डेशन स्टेज	3 से 6 वर्ष	आंगनबाड़ी
	फाउण्डेशन स्टेज	6 से 8 वर्ष	नर्सरी (प्री–प्राइमरी)
3	प्राथमिक शिक्षा	8 से 12 वर्ष	कक्षा 3 से 5
3	मध्यम स्तर	11 से 14 वर्ष	कक्षा 6 से 8
4	अंतिम स्तर	14 से 18 वर्ष	कक्षा 9 से 12

2. **मूल्यों की शिक्षा** – सार्वभौतिक प्रकृति के मूल्यों की शिक्षा जो व्यक्तियों की समानता एवं एकता पर बल देकर अन्धकार, धर्मान्धता, हिंसा, अंधविश्वास और भाग्यवादिता के निराकरण पर बल देती है।

3. **विकलांगों की शिक्षा** – शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सामान्य समुदाय के साथ सहभागी बनाने में बल देना। विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षक, अधिक विकलांगों के लिए जिला स्तर पर छात्रावास तथा स्वैच्छिक पर्यटनों पर विशेष जोर दिया जाएगा।

4. **अल्पसंख्यकों की शिक्षा** – अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा का गुणात्मक और सामाजिक न्याय की दृष्टि से सर्वसाधारण योजना तैयार की जाएगी।

5. **अनुसूचित जातियों व जनजातियों की शिक्षा** – अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास द्वारा गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रलोभन, अनौपचारिक शिक्षा तथा छात्रवृत्ति योजना, निदानात्मक शिक्षण, शिक्षकों की नियुक्ति, छात्रावास सुविधा आदि उपलब्ध कराई जाएगी।

6. **शिक्षण प्रणाली में सुधार** – उच्चतर शिक्षा संस्थानों की उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अनुसंधान एवं सामुदायिक भागीदारी उपलब्ध करवाने के लिए उच्च साधन सम्पन्न एवं बहु विषयक संस्थानों में रूपांतरित

किया जाएगा। पहले सरकारी स्कूलों में प्री–स्कूलिंग नहीं थी, बच्चा 6 वर्ष की आयु से बढ़ना प्रारम्भ करता था लेकिन अब 3 वर्ष से ही शिक्षा ECCE(Early Childhood Care and Education) द्वारा प्रारम्भ (आंगनबाड़ी के माध्यम से) है। पहले जहाँ कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे अब छात्रों को कक्षा 9 से विषय चुनने की आजादी रहेगी। इसके साथ ही 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव कर अब वर्ष में दो बार (सेमेस्टर प्रणाली द्वारा) ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्मेट में परीक्षा आयोजित की जाएगी।

7. **उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार** – इस शिक्षा नीति से पहले की नीति के अन्तर्गत 3 या 4 वर्ष के डिग्री कोर्स में यदि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे डिग्री नहीं मिलती थी जिससे पढ़ने का कोई महत्व नहीं होता था। नई शिक्षा नीति में निम्न परिवर्तन किये गये हैं –

- एक वर्ष की पढ़ाई पर – सर्टिफिकेट
- दो वर्ष की पढ़ाई पर – डिप्लोमा
- तीन या चार वर्ष पर – डिग्री

इसके अलावा जो छात्र हायर एजुकेशन नहीं चाहते है उनके लिए ग्रेजुएशन डिग्री 3 वर्ष की है किन्तु शोध अध्ययन करने वालों के लिए ग्रेजुएशन डिग्री 4 वर्ष की रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एक वर्ष बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प रहेगा तथा इसमें 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जा रहा है।

8. **शिक्षकों से सम्बन्धित सुधार** – शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा तथा पदोन्नति भी अब योग्यता (शैक्षणिक प्रशासन व समय–समय पर कार्य प्रदर्शन का आंकलन) आधारित होगी। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक (NPST) तैयार किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक–छात्रों का अनुपात 30:1 से कम हो तथा सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में यह अनुपात 25:1 से कम हो।

प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षित होगी कि वह स्वयं व्यावसायिक विकास के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष 50 घण्टों का सतत् व्यावसायिक विकास (CPD) कार्यक्रम में हिस्सा ले साथ ही शिक्षकों को गैर–शिक्षण गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यों में शामिल न करने का सुझाव भी दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा (NCERT) के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCFTE-2021) का निर्माण किया गया है।

9. **त्रिभाषा सूत्र क्रियान्वयन सम्बन्धी सुधार** – राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में त्रिभाषा सूत्र यानि कि हिन्दी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई करवाई जाएगीं इसके तहत कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में करवाई जाएगी जिसमें अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता (मैक्याले पद्धति) समाप्त होगी। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परन्तु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव को थोपा नहीं जायेगा। ई–पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। बधिर छात्रों के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। 9वीं कक्षा से विद्यार्थी को विदेशी भाषाओं को भी सीखने का विकल्प मिलेगा।

10. **उच्च शिक्षा एवं खुला विश्वविद्यालय** – उच्च शिक्षा कार्यक्रमों को विशेषज्ञता की मांग को ध्यान में रखते हुए पुनर्गठित किया जायेगा। विश्वविद्यालय में शोध के लिए अधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहु–विषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित किया जायेगा। Higher Education Commission of India (HECI) के कार्यों के प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिये चार संस्थानों/निकायों का निर्धारण किया गया है।

- विनिमय हेतु – राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (NHERC)
- मानक निर्धारण हेतु – सामान्य शिक्षा परिषद (GEC)
- वित्त पोषण हेतु – उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (HEGC)
- प्रत्यायन हेतु – राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद् (NAC)

1985 में स्थापित इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय को समृद्ध किया जाएगा। देश के जो युवा किसी संस्था में नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर सकते उन्हें NIOS (National Institute of Open Schooling) और राज्यों के ओपन स्कूलों द्वारा चलाए जा रहे ODL (Open and Distance Learning) कार्यक्रम से जोड़कर पढ़ाया जाएगा। कक्षा 3, 5 व 8 के लिए राष्ट्रीय खुला विद्यालय संस्थान (NIOS) के द्वारा ओपन लर्निंग की व्यवस्था की जायेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 से सम्बन्धित प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित है –

1. **महंगी शिक्षा**– नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था महंगी होने की संभावना है। परिणामस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।

2. **शिक्षा का संस्कृतिकरण**– दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि त्रि–भाषा सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। इस सिलसिले में तमिलनाडु सरकार का ताजा कदम चिंता बढ़ाने वाला है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में NEP लागू नहीं करने का फैसला किया है। इसके बाद विपक्षी पार्टियों की हुकूमत वाले दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही फैसले लिए जाने की आशंका बढ़ गई है। जाहिर है NEP को जमीन पर उतारने के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच के आंकड़े ठीक करना निहायत जरूरी है।

3. **उच्च अध्ययन में ड्रॉप आउट्स बढ़ने की संभावना**– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के इच्छुक छात्रों को चार साल की पढ़ाई करनी होती है, जबकि कोई भी आसानी से दो साल में अपनी डिप्लोमा की डिग्री पूरी कर सकता है। यह छात्र को पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

4. **फण्डिंग सम्बन्धी जांच का अपर्याप्त होना**– कुछ राज्यों में अभी भी शुल्क सम्बन्धी विनियमन मौजूद है, लेकिन ये नियामक, प्रक्रियाएं असीमित दान के रूप में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ है।

5. **वित्तपोषण**– वित्तपोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में GDP के प्रस्तावित 6 प्रतिशत खर्च करने की इच्छाशक्ति कितनी सशक्त है। ये अजीब विडंबना है

कि जिस साल NEP का आगाज हुआ उसी साल केन्द्रीय बजट में शिक्षा क्षेत्र के आवंटन में कमी आ गई। 2020–21 में केन्द्र का शिक्षा बजट 99311 करोड़ रू. था जिसे 2021–22 में 6 प्रतिशत घटाकर 93224 करोड़ रू. कर दिया गया।

6. **संसद की अवहेलना**– विपक्ष का आरोप है कि भारतीय शिक्षा की दिशा तय करने वाली इस नीति को अनुमति देने में संसद की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया। पूर्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी जो संसद के द्वारा लागू की गई थी।

7. **मानव संसाधन की कमी**– वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है, ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएं भी है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष की दृष्टि से कहे तो NEP 2020 सचमुच हर लिहाज से एक क्रांतिकारी दस्तावेज है इस नीति के तहत तमाम दूसरे मसलों के साथ–साथ शैक्षणिक मुद्दों और ढांचागत विषमताओं के निपटारे पर जोर दिया गया है इसमें 21वीं सदी में भारत की जरूरतों के मद्देनजर शिक्षा को व्यापक और सुलभ बनाने और छात्रों को भावी मांग के हिसाब से तैयार करने का खांका खींचा गया है इसके साथ ही NEP के सामने शिक्षा जगत की अनेक समस्याओं से निपटने की कठिन चुनौती भी है। निश्चित रूप से भारत अपनी युवा आबादी का लाभ उठाना चाहता है। साथ ही तेज गति से बढ़ती ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था में पैदा होने वाले अवसरों को भी हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते है। ऐसे में नई शिक्षा नीति का प्रभावी रूप से अमल करना निहायत जरूरी हो जाता है NEP देश की कायापलट करने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि महामारी से जुड़ी तमाम चुनौतियों के बावजूद केन्द्र सरकार ने इसकी गंभीरता और मकसद को समझते हुए तत्काल कई कदम उठाए है हालांकि अभी NEP को एक लम्बा रास्ता तय करना है राज्य, जिला और निजी क्षेत्र समेत विभिन्न सम्बन्धित पक्षों के बीच तालमेल और सहयोग कायम करने की जरूरत होगी इसके साथ ही राज्यसत्ता की कमजोर क्षमता और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं से भी पार पाना होगा भारत का शैक्षणिक तंत्र नए विचारों और नवाचारों को आसानी से स्वीकार नहीं करता। इस लिहाजे से ठोस कदम की जरूरत होगी।

संदर्भ

1. www.drishtias.com दृष्टि दा विजन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति : महत्व व चुनौतियां, 31 जुलाई 2020
2. www-bbc.com-/hindi/india-53581084 (नई शिक्षा नीति, 29 जुलाई, 2020)
3. www.uttamhindi.com
4. पंचौली, मुकेश (2022), "शैक्षणिक प्रबन्धन एवं प्रशासन", च्यवन प्रकाशन, जयपुर
5. Jakharana, Ajay and Choudhary, Mehtab (2022) : Rath Educational Management and Administration, Rath Publication
6. यादव, एस.एस. (2022), "शैक्षिक प्रबन्धन", कलाम पब्लिकेशन, सीकर
7. https://www.bbc.com/hindi/india-53581084
8. www.dristitias.com नई शिक्षा नीति, 25 अगस्त, 2020
9. www.uttamhindi.com (नई शिक्षा नीति–नए भारत की नींव, 2 अगस्त, 2020)
10. https://www.education.gov.in राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020